



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 106]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 1983/आषाढ़ 7, 1905

No. 106]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 1983/ASADHA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 21-आई०टी०सी० (पी०एम०)/83

नई दिल्ली, 28 जून, 1983

विषय: 1982-83 के लिए येन 1.5 बिलियन जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से भारत में छोटे आकार की इस्पात की छड़ों और पत्तनों पर माल लाने-ले-जाने के लिए उनकी आवश्यक सेवाओं के आयात के लिए लाइसेंस शर्तें।

मिसिल सं० आई० पी० सी०/23/2/83.—1982-83 के लिए जापान से भारत में छोटे आकार की इस्पात की छड़ों और पत्तनों पर माल लाने-ले-जाने के लिए उनकी आवश्यक सेवाओं के आयात के लिए येन 1.5 बिलियन दिनांक 1-2-1983 जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत आयात लाइसेंस जारी करने के लिए लागू शर्तें जैसी इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, उन्हें जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है।

पी० सी० जैन, मुख्य नियंत्रक
आयात-निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय, सार्वजनिक सूचना सं० 21-आई०टी०सी० (पी०एम०)/83
दिनांक 28 जून, 1983 का परिशिष्ट

1982-83 के लिए येन 1.5 बिलियन जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से भारत में छोटे आकार की इस्पात की छड़ों और पत्तनों को यातायात के लिए आवश्यक उनकी सेवाओं के आयात के लिए लाइसेंस शर्तें।

खंड-1 सामान्य शर्तें:

1(1) 1982-83 के लिए येन 1.5 बिलियन (लागत एवं भाड़ा) की जापानी अनुदान सहायता का उपयोग भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, द्वारा भारत में छोटे आकार की इस्पात की छड़ों और पत्तनों में यातायात की आवश्यक उनकी सेवाओं के आयात के लिए जापानी संभारकों को बिल्टीय भुगतान के लिए किया जाएगा। नई अनुदान सहायता 31-3-1984 तक वैध है।

1(2) बैंक ऑफ इंडिया टोकियो को भुगतान किए जाने वाले सभी बैंक प्रभार सामान्य बैंक प्रणालियों के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे। भारतीय अधिकर्ता के कमीशन का भुगतान, यदि कोई हो तो, भारत में अधिकर्ता को भारतीय रूप में किया जाना चाहिए।

1(3) इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत इस्पात की छड़ों और पत्तनों अनुबंधी सेवाओं की अधिप्राप्ति केवल जापान से ही की जाएगी।

1(4) संविदा में भुगतान की व्यवस्था मकब आधार अर्थात् बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो की जापानी संभरको द्वारा लदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर करना चाहिए। वितरण की अवधि निम्न प्रकार से होनी चाहिए "वितरण 15-3-1984 तक पूर्ण हो जाना चाहिए"।

1(5) संविदा का मूल्य (केवल लागत एवं भाड़े के आधार पर) येन में येन का अंश हटा देना चाहिए) प्रवर्धित किया जाना चाहिए और यदि कोई हो तो, भारतीय अधिकता या कमीशन निकाल देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में भारतीय अधिकता का मूल्य किसी अन्य मुद्रा में प्रवर्धित नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ पर्यन्त निशुल्क लागत एवं भाड़ा राशि अलग से बर्खास्ति जानी चाहिए, किंतु संविदा में यह स्वतः स्पष्ट होना चाहिए कि भाड़े का भुगतान वास्तविक आधार पर किया जाएगा अथवा उसमें बर्खास्ति गया भाड़ा वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त भुगतान की राशि होगा।

1(6) क्रय संविदा जापानी राष्ट्रियों के साथ केवल जापानी येन में की जानी चाहिए। खंड-2 संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान स्पष्ट रूप से समाविष्ट होने चाहिए —

2(1) ठेके की व्यवस्था 1982-83 के लिए येन 1 5 बिलियन के अनुदान सहायता के अनुसार भारत और जापान की सरकारों के बीच 1 फरवरी, 1983 का हुए समझौते के अनुसार होनी चाहिए और दोनों सरकारों के अनुमोदन के अधीन होगी।

2(2) संभरणों को भुगतान 'भुगतान के प्राधिकार' (ए/पी) के माध्यम से किए जाएंगे। जो 1982-83 के लिए जापान अनुदान सहायता के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो के लिए सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाएंगे।

2(3) जापानी संभरण ऐसी भूचमाओं एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होंगे जो एक ओर भारत सरकार एवं दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित होंगे।

2(4) जापानी संभरण भारतीय वृत्तावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत हैं और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय वृत्तावास, टोकियो को शामिल भाग की सुपुर्गों के कार्यक्रम से अवगत कराएगा और पोत लदान से कम से कम 8 सप्ताह पूर्व भारतीय वृत्तावास को सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके। विशेष मामलों में, जहाँ आयातक इच्छुक हों, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरण को प्रत्येक पोतलदान के पश्चात् आवश्यक धीरे देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय वृत्तावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खंड-3 भारत और जापान की सरकारों द्वारा ठेके का अनुमोदन —

3(1) जैसे ही आवेशों को अंतिम रूप दे दिए जाते हैं, आयातक को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियाँ जापानी संभरणों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आवेश के साथ जापानी संभरण द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आवेश की चार प्रतियाँ या सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबंध-1 के प्रपत्र में "(ए/पी) जारी करने के लिए आवेदन" की 2 फोटो प्रतियाँ अवर सचिव (टी ए) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, मार्थ ब्लॉक नई दिल्ली को भेजनी चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषय वस्तु या उसकी कीमत के आवश्यक आशोधनों से उत्पन्न सभी संविदा सशोधनों के लिए भी लागू होगी।

3(2) वित्त मंत्रालय (डीईए) जापान अनुभाग 1982-83 के लिए 1 5 बिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अधीन वित्तदान देने के लिए संविदा की एक प्रति जापान सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा, और इसी के साथ-साथ उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों का एक सेट सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के वृत्तावास, टोकियो को भी भेजा जाएगा।

3(3) जापान सरकार के ठेका अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, मार्थ ब्लॉक का जापान अनुभाग उनकी सूचना सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, ससद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को देगा जोकि जापानी संभरण को भुगतान करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया टोकियो को अनुबंध 2 के अनुसार एक "भुगतान प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी करेगा। प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्रतियाँ भारत का वृत्तावास टोकियो, आयातक, भारत के आयातक के बैंक और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के जापान अनुभाग को भेजी जाएंगी।

3(4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) प्राप्त करने पर बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो जापान सरकार, भारत का राजवृत्तावास टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से जापानी संभरण की अवगत कराएगा।

3(5) पोतलदान करने के बाद जापानी संभरण अपने बैंकों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक ऑफ इंडिया, दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को जापानी संभरण को अपने बैंकों के माध्यम से रिहा करेगा।

3(6) जापानी संभरण को भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो की देय बैंक खर्च भारत सरकार के लेखों को प्रभावित किए बिना सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से भारत में आयातक से संबंध बैंक द्वारा बैंक ऑफ इंडिया टोकियो को धन परेषित कर के निर्णीत किया जाएगा।

खंड-4 जमा करने का दायित्व

4(1) मूल विनियम पोत परिवहन दस्तावेज निरपवाद रूप से बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के संबंध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जो अनुबंध-1 (ड) में उल्लिखित है, की शाखा होगी। इस बैंक की दस्तावेजों के ये विनियम दस्तावेज केवल इस बात का सुनिश्चय कर लेने के बाद ही संबंध आयातक को देने चाहिए कि जापानी संभरण की चुकाई गई येन धनराशि के बराबर रुपया निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार के लेखों में जमा करा दिया गया है —

"आयातक अर्थात् भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल) आयातित इस्पात की छड़ों की लागत जमा करायेगा जिसकी गणना इस्पात की मूल कीमत के आधार पर होगी, इसमें से आयातक द्वारा चुकाई गई सीमा शुल्क कर की धनराशि घटा दी जाएगी और लागत एवं भाड़ा मूल्य की 4% धनराशि सेवा खर्च के रूप में और अन्य खर्च जैसे संचालन, रेलवे भाड़ा आदि घटा दिए जाएंगे। आयातित इस्पात की छड़ों के लागत एवं भाड़ा मूल्य और आयातक द्वारा उपर तथा उल्लिखित वास्तव में जमा कराई गई धनराशि दोनों के बीच में आने वाले अंतर के बाद में इस्पात विभाग द्वारा सी ए एंड ए को देय सहायता की धनराशि में सामंजस्य कर दिया जाएगा और 1983-84 के बजट में लगाया जाएगा। इस्पात विभाग और सी ए एंड ए के बीच समझौते की जाने योग्य धनराशि पर और भारतीय बैंक टोकियो द्वारा जापानी संभरण को किए जाने योग्य भुगतान के बीच की अवधि के लिए और उनके द्वारा भारत में अपने बैंकों में किए गए वास्तविक निक्षेप का सार्वजनिक के बीच की अवधि के लिए आयातक को किसी भी प्रकार का ब्याज प्रभार नहीं देना पड़ेगा।"

येन भुगतान के समतुल्य रूप की गणना करने के लिए अपनाई गुरु मुद्रा विनियम की वर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं० 8-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 17-1-76 में यथा निर्धारित मुद्रा विनियम की प्रचलित मिश्रित वर या समय-समय पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा अधिसूचित वर होगी। इस संबंध में कोई भी परिवर्तन जैसे और जब भी आवश्यक होंगे, अधिसूचित किया जाएगा। संबंध भारतीय बैंक का इस बात का सुनिश्चय करने का दायित्व होगा कि आयातकों को आयात वस्तावेज सौंपने से पूर्व वे धनराशि सरकारी लेख में सही रूप से जमा करा दी गई हैं। आयातकों को यह भी सुनिश्चय करना चाहिए कि अपने बैंकों से वस्तावेज लेने से पहले वे धनराशि सरकारी लेख में सही रूप से जमा करा दी गई हैं। लेखा शीर्ष जिसमें उपर्युक्त रूपया जमा निक्षेप किया जाएगा वह है "के डिपॉजिट्स एंड एक्वासिज-843-सिविल डिपॉजिट्स-डिपॉजिट्स फार परचेजिज एट्टेस्टा, एक्वा-परचेजिज अंडर ग्रांट ऐंड फ्राम दि गवर्नमेंट ऑफ जापान फार 1982-83 ग्रांट फार परचेजिज ऑफ दि स्टील आइटम्स।"

4(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सीस हजारी दिल्ली में या यदि, यह सम्भव न हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सीस हजारी शाखा दिल्ली-8 (आदेशित और प्राप्त) के नाम और उसको वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इसकी सहायक शाखा या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (आदेशक) से प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सरकार के खाते में जमा करानी चाहिए। सार्वजनिक सूचना-184 आईटीसी (पीएन)/68 दिनांक 30-8-68, सं०-233 आईटीसी (पीएन)/68 दिनांक 24-10-68 और सं० 132-आईटीसी (पीएन/71) दिनांक 5-10-71 में दृष्टव्य है।

4(3) चालान के विभिन्न कालम भरते समय आयातकों/उनके बैंकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 132-आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 5-10-71 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना चालान के "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण इमीरे" कालम में निरपवाद रूप से निविष्ट की गई है। खजाना चालान में निम्नलिखित ग्योरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :-

- (क) वित्त मंत्रालय के 'ए/पी' (भुगतान के लिए प्राधिकारी पत्र) की सं० एवं दिनांक।
- (ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की वर के साथ-साथ निक्षेप किए जाने हैं।
- (ग) जापानी संभरक को भुगतान की तिथि।
- (घ) निक्षेप की गई कुल धनराशि।

उसके पश्चात् सी ए ए एंड ए द्वारा जारी किए गए ए/पी (भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र) का संबंध देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान, रूपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी ए ए एंड ए को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी: भारत में आयातक के बैंक की यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो में भुगतान की सूचना और विनियम पोत परिवहन दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर रूपया निरपवाद रूप से जमा कर दिया गया है और यह कि इसके तुरन्त बाद इसकी सूचना सी ए ए एंड ए वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को दे दी गई है।

4(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक की लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पर रूपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठीकरण करना चाहिए और अपेक्षित "एम" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई को भेजना चाहिए।

खंड-5 विविध व्यवस्थाएं

5(1) अनुदान सहायता के उपयोग पर रिपोर्टें

आयातक को पोतलाभ और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में ए/पी जारी हो जाने के पश्चात् एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, यू.सी.ओ. बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

5(2) संभरकों की विशेष शर्तें अधिसूचित करना

आयातक को इस अनुदान सहायता के अधीन इस्पात की मरों के आयात के सम्बन्ध में उन विशेष प्रावधानों से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लेन-देन में संभरक पर प्रभाव डालते हों।

5(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि आयातकों और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उनके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें आयातक द्वारा अनुबंध-1 में "भुगतान की शर्तों" के अन्तर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट करनी चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद निपटाने से संबंधित व्यवस्थाएं शामिल हानी चाहिए।

5(4) भविष्य अनुदेश

जापान से 1982-83 के लिए अनुदान सहायता के अधीन आयातों से उत्पन्न या उनके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी भी मामले या सभी मामलों के संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों को और सभी दायित्वों का आयातक को तुरन्त पूरा करना होगा।

5(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त अनुच्छेदों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

5(6) अनुबंधों की सूची :-

अनुबंध 1:-ए/पी जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र

अनुबंध 2:-ए/पी का प्रपत्र

अनुबंध-1

"भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र"

सं०

दिनांक

सेवा में,

सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,

यू.सी.ओ. बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,

संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय :- 1982-83 के लिए जापान अनुदान सहायता के अधीन जापान से भारत में छोटे आकार की इस्पात की छड़ों और उनके यातायात के लिए आवश्यक सेवाओं का आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से इस्पात की मरों के आयात के संबंध में हम आपको निम्नलिखित ग्योरे "जते हैं जिससे कि आप सम्बद्ध जापानी संभरक के पक्ष में बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी कर सकें :-

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता
 (ख) अधिप्राप्ति के तरीके—क्या यह प्रत्यक्ष खरीद पर आधारित है या सीमित खुली निविदा पर आधारित है। इस मामले में कारणों सहित यह निदिष्ट करना है कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।
 (ग) माल का संक्षिप्त विवरण
 (घ) माल का उद्गम देश
 (ङ) संविदा का कुल लागत और भाड़ा मूल्य (येन में)
 (च) यदि कोई हो तो भारतीय रुपए में भारतीय एजेंट के कर्मियों की धनराशि (येन में)
 (छ) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।
 (ज) जापानी सभरको के साथ की गई संविदा की संख्या और दिनांक।
 (झ) जापानी सभरको का नाम और पता।
 (ञ) वे भुगतान शर्तें और सम्भावित स्थिति जिनको संविदाओं के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे।
 (ट) माल की सुपुर्वगी पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथियाँ।
 (ठ) बैंक आफ इंडिया, टोकियो का भुगतान करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट का संख्या और उनके निपटान वगैरह)।
 (ड) पोत लवान अनुदेश (अनुमेय या गैर अनुमेय वाहनान्तरण/आंशिक पात लवान निदिष्ट काजिए)
 (ड) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।

भवदीय,
 अनुबंध-3

सं एक

भारत सरकार

वित्त मन्त्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया,

टोकियो शाखा,

टोकियो (जापान)

विषय.—1982-83 के लिए येन 1 5 बिलियन की जापान अनुदान सहायता के अधीन छोटे आकार की इस्पात की छड़ों के आयात के लिए भुगतान प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ . . . को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एस्केन्डर परिशिष्ट में दिए गए यथा सलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्वश्रेष्ठ को . . . येन धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2 कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/वी) की पाबली के बारे में सभरको को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार, आयातक बैंक, भारत के राजभूतावास, टोकियो और इस मन्त्रालय को पृष्ठांकित की जाए।

3 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा संकेतित लवान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4 आयातक द्वारा आपको दस्तावेज सभरको एच बैंकरो के प्रभार को भेजने और के लिए भाड़े सहित अथवा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े आयातक के बैंक द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

5 जैसे ही आपानी सभरको द्वारा प्रस्तुत किए गए लवान दस्तावेज आदि के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मन्त्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए।

6 इस मन्त्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

7. यह भुगतान प्राधिकार पत्र . . . तक वैध रहेगा।

भवदीय,

(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित .—

1 आयातक . . . उनके पत्र सं . . . दिनांक के संबंध में।

2 आयातक का बैंक . . . उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इंडिया, टोकियो, साथ से दस्तावेज प्राप्त करने पर जापानी सभरको को येन भुगतान में बराबर कपया जमा करने की व्यवस्था करे। सभरको का चुकायी गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं० 8-आईटीसी(पीएन)/76 दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार विधेय। सभरको का भुगतान करने तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा-मूल्य निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया सीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसकी अनुपूर्व सस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीय-कृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया, सीस हजारी शाखा, दिल्ली-8 (आदेशित और आस्था) के नाम में और उसको देय दर्शनी हुई। के माध्यम से करनी चाहिए इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 233-आईटीसी(पीएन)/68 दिनांक 24-10-68, सं० 132-आईटीसी(पीएन)/71 दिनांक 5-10-71, सं० 74-आईटीसी(पीएन)/74 दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आईटीसी(पीएन)/76 दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर बिसाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट्स एंड एक्वासिज 843 सिविल डिपोजिट्स डिपोजिट्स फार परचेजिड एटसेक्टर एक्वा-परचेजिड ग्राण्ड एंड फाम वि गवर्नमेन्ट आफ जापान फार 1982-83 है और निस्तुत लेखा शीर्षक" "छोटे आकार की इस्पात की छड़ों के आयात के लिए जापान से येन 1 5 बिलियन अनुदान सहायता है" "येन 50 मिलियन ग्रांट एंड फार परचेज आफ वि जिमनस्टिक एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेन्ट/सप्लाइड फार वि परचेज आफ प्रोमोटींग फिजिकल एज्युकेशन एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेन्ट इन इंडिया" है।

जिन मामलों में मुख्य कपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, सीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं० 132-आईटीसी(पीएन)/71 दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकव जमा किया जाता है उनमें घानान की मूल रूप में एक प्रतिनिधि बैंक आफ इंडिया टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अत्रेण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी —

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
और मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
पहली मंजिल, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग,
ससद मार्ग, नई दिल्ली-110001

जिस मामले में तुल्य रूप का ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक
1-10-1968 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी
उपस्थिति पर पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में, व्याज की
धनराशि और जिस अवधि के लिए व्याज की गणना की गई है
बुकाई नई रूप जमा किए गए तुल्य रूप का पूरा गौरा इस विभाग
और उसके से
को भेजना चाहिए।

समुद्रमार्ग सभ्यता के बैंक के खर्चों सहित यदि कोई हो तो, बैंकिंग
खर्च और बैंक आक इंडिया, टोकियो आच के अन्य खर्च इंडियन बैंक
आर बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित कि
जमने।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो।

5. अन्तर सचिव (ई ए) कक्षा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग
नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 21-ITC(PN)|83

New Delhi, the 28th June, 1983

Subject: Licensing Conditions for import of small size steel bars and services necessary for the transportation thereof to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid for 1982-83 of Yen 1.5 billion.

File No. IPC|23(2)|83.—The terms and conditions governing the licensing conditions for import of small size steel bars services necessary for the transportation thereof to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid for 1982-83 of Yen 1.5 billion dated 1-2-1983 as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

P.C. JAIN, Chief Controller
Imports & Exports

Appendix to Ministry of Commerce Public
Notice No. 21-ITC(PN)|83 dated 28th June, 1983

Licensing Conditions for import of small size steel bars & services necessary for the transportation thereof to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid for 1982-83 of Yen 1.5 billion.

Section I-General Conditions

I(i) The Japanese Grant Aid for 1982-83 of Yen 1.5 billion (C&F) is intended to be used for financing payments to Japanese Suppliers for import of small size steel bars and services necessary for their transportation to ports in India by

the Steel Authority of India Ltd. This grant aid is valid upto 31-3-1984.

I(ii) All banking charges payable to the Bank of India, Tokyo may be remitted through normal banking channels. Payment towards Indian Agent's Commission, if any, should be made in Indian rupees to the agents in India.

I(iii) The steel bars and services incidental thereto should be procured only from Japan under this Grant Aid.

I(iv) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo. It should also provide for the period of delivery as follows :—

"delivery to be completed by 15-3-1984".

I(v) The contract value (C&F basis only) should be expressed in Yen (fraction of yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's Commission, if any in no circumstances the contract value should be expressed in any other currency. The FOB cost & freight amount should be shown separately but it should be clarified in the contract itself whether the freight will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated therein would be the amount payable irrespective of the actual charges.

I(vi) The purchase contract should be entered into only in Japanese Yen with the Japanese nationals.

Section II.—The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

II(i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 1st February, 1983 between the Governments of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 1.5 billion for 1982-83 and will be subject to the approval of both the Government.

II(ii) Payments to the suppliers shall be made through an 'Authorisation to Pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1982-83.

II(iii) The Japanese suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government or Japan on the other.

II(iv) The Japanese supplier agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this pur-

those he would keen the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer requires it this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section-III Contract Approval by Governments of India and Japan.

III(i) As soon as the orders are finalised, the importer should forward to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs Ministry of Finance, North Block, New Delhi 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the Japanese supplier supported by order confirmation in writing by the Japanese supplier or their photo copies complete in all respect together with two copies of the "Request for issue of A/P" in the form at Annex I. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

III(ii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract to the Government of Japan for their approval for financing under the Japanese Grant Aid for 1982-83 of Yen 1.5 billion, and one set of the documents mentioned in (i) above will also be sent to the CAA&A and Embassy of India in Tokyo simultaneously.

III(iii) On receipt of the contract approval from the Government of Japan, the Japan Section of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block will inform the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 of the same who will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form of Annexure II for making payment to the Japanese supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

III(iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the Japanese supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo the importers' Bank in India and the C.A.A.&A.

III(v) The Japanese supplier shall, after effecting shipment present through his bankers the documents specified in the A/P to the BOI, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, will release the amount specified in the documents to the Japanese supplier through his bankers.

III(vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for arranging the payment to the Japanese supplier shall be settled by the importer's bank in India by remittance to the BOI, Tokyo through normal banking channels to the Government of India's account.

Section IV Responsibility for rupee deposit

IV(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (n) in Annexure-I who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen Payments made to the Japanese supplier is deposited into Government of India account as described below :—

The importer i.e. Steel Authority of India Ltd. (SAIL) would deposit the cost of the imported steel bars computed on the basis of the indigenous price of steel reduced by the amount of customs duty paid by it plus 4% of the service charges on C&F value and other charges like handling, railway freight etc. The difference between the C&F value of the imported steel bars and the amount actually deposited by the importer as stated above would be later adjusted in the subsidy payable by the Department of Steel to CAA&A and budgeted for in 1983-84. No interest charges would be payable by the importer on the amount which will be adjusted between the Deptt. of Steel and CAA&A and for the period of difference between the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Japanese supplier and the date of actual rupee deposits made by them with their bankers in India."

The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No.8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in

this regard will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Accounts before the import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers.

The Head of Account to which the above rupee deposit should be credited is "K-Deposits and Advances-843-Civil Deposits-Deposits for purchases etc., abroad-purchase under Grant Aid from the Government of Japan" for 1982-83, Grant for purchase of the steel items.

IV(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Banks of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC (PN)|68 dated 30-8-1968 No. 233-ITC (PN)|68 dated 24-10-1968 and No. 132-ITC (PN)|71 dated 5-10-1971.

IV(iii) While filling in the various columns in the Challan it should be ensured by the Importers|their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC (PN)|71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury challans :

- (a) Ministry of Finance 'A|P' (Authorisation to Pay) No. and date.
- (b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the Japanese supplier.
- (d) Total amount deposited.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A|P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payment and

negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is informed immediately thereafter.

IV(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section V Miscellaneous provisions

V(i) Reports on the utilisation of the Grant Aid

The importer should send a monthly report after the A|P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

V(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions

The importer should apprise the supplier of any special provisions in the import of steel items under this Grant Aid which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

V (iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the importer and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of Payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

V(iv) Future Instructions

The importer shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the imports and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1982-83 from Japan.

V(v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

V(vi) List of Annexures :

Annexure I—Request for issue of A|P

Annexure II—Form of A|P.

ANNEXURE I

“REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORITY TO PAY”

No.

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street, New Delhi-110001

Subject : Import of small size steel bars & services necessary for the transportation thereof to ports in India from Japan under the Japanese Grant Aid for 1982-83.

Sir,

In connection with the import of steel items from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A/P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Japanese supplier concerned :—

- (a) Name and Address of the Indian importer.
- (b) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or limited open tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (c) Brief description of the goods.
- (d) Origin of the goods.
- (e) Gross C & F Value of contract (in Yen).
- (f) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any payable in Indian rupees.
- (g) Net C&F Value (in Yen) for which the A/P is required.
- (h) Number & date of the contract with Japanese Suppliers.
- (i) Name and Address of the Japanese Supplier.
- (j) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (k) Expected date of completion of deliveries.
- (l) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(m) Shipment instructions (indicate if transshipment/partshipment permitted or not permitted).

(n) Name and Address of the Importer's bank in India.

Yours faithfully,

ANNEXURE II

No. F

Govt. of India

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Bank of India
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan)

Subject : Import of small size steel bars under Japanese Grant Aid of Yen 1.5 billion for 1982-83—Issue of Authorisation to Pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen to M/s. as per details given in the Appendix.

2. Please advise the Supplier of the fact of receipt of this Authorisation to Pay (A/P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A/P will be made on the basis of shipping documents as indicated in the Appendix.

4. Banking charges including charges for handling documents, and charges of Overseas Suppliers, Bankers if any, payable to you by the importer, will be settled directly by the importer's bank.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents etc. presented by the Japanese supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's Bank.

6. No amendment to this A/P may be advised in the absence of a specific authority from this Ministry.

7. This A/P will remain valid upto ———.

Yours faithfully,
Accounts Officer

Copy forwarded to :—

1. Importer— with reference to their letter No. — dated —.

2. Importer's Banker— They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the Japanese suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers in accordance with the Public Notices No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. It should be ensured that those deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-68, No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-76. The head of Account to be credited is 'K-Deposits & Advances-843-CIVIL Deposits—Deposits for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from Govt. of Japan for 1982-83' under detailed head "Yen 1.5 billion grant aid for

import of small size steel bars from Japan".

One copy of the challan in original in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

3. In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited along with the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TA), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

